भारतीय जीवन बीमा निगम

बनाम

जया चंदेल

सिविल (अपील) संख्या 1089/2008

7 फरवरी, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत, पी. सदाशिवम, जेजे.]

बीमा अधिनियम, 1938 - बंद की गई नीतियों का पुनरुद्धार - दावा के लिए - लैप्स हो चुकी एलआईसी पॉलिसी के वार्षिक प्रीमियम को विलंब शुल्क के साथ चेक के माध्यम से बीमित व्यक्ति की मृत्यु से पहले जारी किया लेकिन बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद एल. आई. सी. निगम को प्राप्तः - बंद की गई नीति को निगम द्वारा अनुमोदित और इसे सूचित करने के बाद ही पुनर्जीवित किया जा सकता है - तथ्यों के अनुसार, बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद चेक प्राप्त हुआ था - भुगतान अनुग्रह अवधि से बहुत समय पश्चात किया गया था - धारा 64 वी. बी. भी लागू नहीं था - इस प्रकार, निचले मंचों के दावे को दरकिनार नहीं आदेश को किया।

दिनांक 28.3.1994 को एलआईसी पॉलिसी प्राप्त की और 28.3.1995 पर या उससे पहले वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करने में विफल रहे। पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, वह एक महीने के बाद निष्क्रिय हो गई। एक पी नाम के व्यक्ति ने विलंब शुल्क के साथ वार्षिक प्रीमियम के लिए चेक दिनांक 27.6.1995 को जारी किया। बीमित व्यक्ति की मृत्यु 1.7.1995 को हुई और चेक 12.7.1995 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी-भारतीय जीवन बीमा निगम ने दावे को खारिज कर दिया। मृतक की विधवा

ने एक याचिका दायर की। जिला फोरम, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अभिनिर्धारित किया कि दावे को अस्वीकार नहीं किया जा सकता था।

इसलिए वर्तमान अपील अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1.1 अनुग्रह अवधि एक महीने है और इसलिए राज्य आयोग का यह मानना उचित नहीं था कि भुगतान अनुग्रह अवधि के भीतर किया गया था। शर्त 3 बंद हो चुकी पॉलिसी को फिर से चालू करने से संबंधित है। शर्त को पढ़ने से पता चलता है कि इसे बीमित व्यक्ति के जीवनकाल के दौरान पुनर्जीवित किया जा सकता है। मौजूदा मामले में यह स्वीकृत है कि चेक बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद प्राप्त हुआ था। इसके अलावा पुनरुद्धार तभी प्रभावी होता है जब इसे निगम द्वारा अनुमोदित किया जाता है और बीमाधारक को विशेष रूप से सूचित किया जाता है। वर्तमान मामले में यह स्थिति नहीं है. [पैरा 6] [563-ई, एफ]

1.2. अधिनियम की धारा 43 बीमा अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लेख करती है जो अधिनियम पर लागू होती हैं और धारा 64-वीबी उनमें से एक नहीं है। ऐसा होने पर भी राष्ट्रीय आयोग द्वारा उस प्रावधान की प्रयोज्यता के बारे दिया निष्कर्ष उचित नहीं था। [पैरा 7] [564-जी; 565-ए]

1.3 किसी भी दृष्टि से देखें तो जिला फोरम, राज्य फोरम और राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आदेश कायम नहीं रह सकते और निरस्त किये जाते हैं। [पैरा 8] [565-ए, बी]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1089/2008।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के आर. पी. संख्या 2068/2001 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 17.1.2005 के खिलाफ।

अपीलार्थी की ओर से पी. एस. पटवालिया, इंद्रा साहनी।

प्रत्यार्थी की ओर से प्रगति नीखरा, सूर्यनारायण सिंह और धर्मेंद्र कुमार सिन्हा।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, जे द्वारा दिया गया था।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (संक्षेप में "राष्ट्रीय आयोग") द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया है। राष्ट्रीय आयोग के समक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, शिमला (संक्षेप में 'राज्य आयोग') द्वारा अपील में पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने जिला फोरम, शिमला (संक्षेप में 'जिला फोरम') द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा था।

संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैं कि:

करण सिंह चंदेल (बाद में 'मृतक' के रूप में संदर्भित) ने एक जीवन बीमा पॉलिसी ली थी और 1,50,000/- रुपये की राशि का बीमा कराया था। वार्षिक प्रीमियम रु. 12,821/- देय था। पॉलिसी 28.3.1994 को ली गई थी। वार्षिक प्रीमियम, जिसका भुगतान 28.3.1995 को या उससे पहले किया जाना था, का भुगतान नहीं किया गया। पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, वह एक महीने के बाद निष्क्रिय हो गई। बीमाधारक की मृत्यु 1.7.1995 को हो गई। जोगिन्द्र सहकारी बैंक लिमिटेड पर 12,821/- रुपये की राशि का एक चेक कथित तौर पर प्रीमियम के लिए 189/- रुपये विलंब शुल्क के साथ

दिनांक 27.6.1995 को प्रकाश चंद ठाकुर द्वारा जारी किया गया था। जो दिनांक 12.7.1995 को प्राप्त हुआ। दावेदार यानी मृतक की विधवा के अनुसार, चेक बीमाधारक की मृत्यु से पहले जारी किया गया था और इसलिए, अपीलकर्ता दावे को अस्वीकार नहीं कर सकता था।

3. वर्तमान अपीलकर्ता का पक्ष यह था कि समय पर प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण पॉलिसी समाप्त हो गई थी। इस दलील को जिला फोरम ने इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि चेक 12.7.1995 को जारी होने का दावा किया गया था, लेकिन माना जाता है कि यह उस तारीख से पहले प्राप्त हुआ था। राज्य आयोग ने माना कि किसी भी स्थिति में राशि छूट अवधि के भीतर प्राप्त की गई थी और इसलिए, दावे को अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। तदनुसार अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई। नेशनल फोरम ने यह कहते हुए संशोधन को खारिज कर दिया कि बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64-वीबी (संक्षेप में 'बीमा अधिनियम)') वहां लागू था जहां प्रीमियम डाक मनी ऑर्डर या डाक द्वारा भेजे गए चेक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और जोखिम उस तिथि पर माना जा सकता है जिस दिन मनी ऑर्डर बुक किया जाता है या चेक पोस्ट किया जाता है, जैसा भी मामला हो। इसलिए, यह माना गया कि पुनरुद्धार था। इसने अपीलकर्ता के इस मत को स्वीकार नहीं किया कि पुनरुद्धार किसी के अधिकार का मामला नहीं था।

4. अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कथन किया है कि जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग कुछ प्रासंगिक कारकों पर ध्यान देने में विफल रहे हैं। उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि चेक बीमाधारक द्वारा नहीं बल्कि प्रकाश चंद ठाकुर द्वारा क्यों जारी किया गया था। यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि बाद में पॉलिसी को नियमित करने के लिए एक चेक जारी किया गया था। इसके

अलावा चेक मृत्यु के काफी बाद 12.7.1995 को प्राप्त हुआ था और यह स्वयं यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि चेक बीमाधारक की मृत्यु से पहले जारी नहीं किया गया था। रसीद रजिस्टर का उद्धरण दाखिल किया गया है जिससे पता चलता है कि चेक 12.7.1995 को प्राप्त हुआ था। राज्य आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चेक अनुग्रह अवधि के दौरान जारी किया गया था। यह भी तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि अनुग्रह अवधि 30 दिन है, प्रीमियम 28.3.1995 को देय था और चेक अनुग्रह अवधि से काफी समय बाद जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, धारा 64-वीबी अपीलकर्ता पर लागू नहीं होती है। इस संदर्भ में जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 43 (संक्षेप में 'अधिनियम') की प्रासंगिकता है। पॉलिसी की शर्त 2 का भी संदर्भ दिया गया है।

5. उत्तर में दावेदार के वकील ने कहा कि पॉलिसी की शर्त 2 लागू नहीं है, बल्कि शर्त संख्या 3 लागू है। यह कहा गया है कि कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता क्योंकि बीमाधारक ने चेक पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और केवल इसलिए कि चेक मृतक की मृत्यु के बाद प्राप्त हुआ था जो अपीलकर्ता को वास्तविक दावे को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं देता है।

पॉलिसी की शर्तें 2 और 3 इस प्रकार हैं कि:

"2. प्रीमियम का भुगतान: वार्षिक, अर्ध-वार्षिक या त्रैमासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए एक महीने की अनुग्रह अवधि, जो 30 दिनों से कम नहीं होगी और मासिक प्रीमियम के लिए 15 दिन की अनुग्रह अवधि दी जाएगी। यदि इस अवधि के भीतर और देय प्रीमियम के भुगतान से पहले मृत्यु हो जाती है तब भी पॉलिसी वैध होगी और उक्त प्रीमियम की कटौती के बाद भुगतान की गई बीमा राशि और पॉलिसी की अगली वर्ष गांठ से पहले देय

अवैतनिक प्रीमियम भी।यदि प्रीमियम का भुगतान अनुग्रह अवधि से पहले नहीं किया जाता है तो पॉलिसी समाप्त हो जावेगी। यदि पॉलिसी समाप्त नहीं हुई है और पॉलिसी के तहत मृत्यु के मामले में दावा स्वीकार किया गया है, जहां प्रीमियम के भुगतान का तरीका वार्षिक के अलावा अन्य है, तो अगली पॉलिसी वर्षगांठ से पहले देय होने वाले अवैतनिक प्रीमियम को दावा राशि से काट लिया जाएगा।"

"3. बंद पॉलिसियों का पुनरुद्धार: यदि पॉलिसी समाप्त हो गई है तो इसे बीमित व्यक्ति के जीवन काल के दौरान पुनरुद्धार किया जा सकता है, लेकिन पहले भुगतान न किए गए प्रीमियम की तारीख से 5 साल की अवधि के भीतर और परिपक्वता की तारीख से पहले, निगम की संतुष्टि के लिए निरंतर बीमा योग्यता का प्रमाण और निगम द्वारा समय-समय पर अर्धवार्षिक रूप से तय की जाने वाली दर पर ब्याज सहित प्रीमियम के सभी बकाया का भुगतान जमा करना होगा। बंद की गई पॉलिसी का पुनरुद्धार करने के आवेदन को निगम स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है। बंद की गई पॉलिसी का पुनरुद्धार तभी प्रभावी होगा जब इसे निगम द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और विशेष रूप से बीमित व्यक्ति को सूचित किया जाएगा।"

6. अनुग्रह अवधि एक महीने है और इसलिए राज्य आयोग का यह मानना उचित नहीं था कि भुगतान अनुग्रह अवधि के भीतर किया गया था। शर्त 3 बंद हो चुकी पॉलिसी को फिर से चालू करने से संबंधित है। शर्त को पढ़ने से पता चलता है कि इसे बीमित व्यक्ति के जीवनकाल के दौरान पुनर्जीवित किया जा सकता है। मौजूदा मामले में यह स्वीकृत है कि चेक बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद प्राप्त हुआ था। इसके

अलावा पुनरुद्धार तभी प्रभावी होता है जब इसे निगम द्वारा अनुमोदित किया जाता है और बीमाधारक को विशेष रूप से सूचित किया जाता है। वर्तमान मामले में यह स्थिति नहीं है।

इसके अलावा अधिनियम की धारा 43 इस प्रकार है:

43. बीमा अधिनियम का लागू होना।

(1) बीमा अधिनियम की निम्नलिखित धाराएं, जहां तक संभव हो, निगम पर वैसे ही लागू होंगी जैसे वे किसी अन्य बीमाकर्ता पर लागू होती हैं :- धारा 2, 2 बी, 3, 18, 26, 33, 38, 39, 31, 45, 46, 47 ए, 50, 51, 52, 110 ए, 110 बी, 110 सी, 119, 121, 122 और 123.

(2) केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तुरंत बाद, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्देश देगी कि बीमा अधिनियम की निम्नलिखित धाराएं निगम पर ऐसी शर्तों और संशोधनों के अधीन लागू होंगी जो अधिसूचना में उल्लेखित हैं।:- धारा 2 डी, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 27 ए ,28 ए, 35, 36, 37, 40, 40 ए, 43, 44, 102 से 106, 107 से 110, 111, 113, 114 और 116 ए।

1 [(2 ए)] बीमा अधिनियम की धारा 42 किसी भी व्यक्ति को निगम के लिए जीवन बीमा व्यवसाय की मांग करने या खरीदने के उद्देश्य से एक एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस जारी करने के संबंध में प्रभावी होगी, जैसे कि एक संदर्भ इसकी उपधारा (1) में नियंत्रक

द्वारा इस संबंध में अधिकृत निगम के एक अधिकारी का संदर्भ शामिल है।]

(3) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सभी या कोई बीमा अधिनियम उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट के अलावा अन्य ऐसी शर्तों और संशोधनों के अधीन निगम पर लागू होंगे जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

(4) उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के तहत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी होने के बाद जितनी जल्दी हो सके संसद के दोनों सदनों के समक्ष कम से कम तीस दिनों के लिए रखी जाएगी, और ऐसे संशोधनों के अधीन होगी। जैसा कि संसद उस सत्र के दौरान कर सकती है जिसमें इसे रखा गया है या उसके तुरंत बाद के सत्र में।

(5) इस अनुभाग में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, बीमा अधिनियम में निहित कोई भी चीज़ निगम पर लागू नहीं होगी।

7. अधिनियम की धारा 43 बीमा अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लेख करती है जो अधिनियम पर लागू होती हैं और धारा 64-वीबी उनमें से एक नहीं है। ऐसा होने पर भी राष्ट्रीय आयोग द्वारा उस प्रावधान की प्रयोज्यता के बारे दिया निष्कर्ष उचित नहीं था।

8. किसी भी दृष्टि से देखें तो जिला फोरम, राज्य फोरम और राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आदेश कायम नहीं रह सकते और निरस्त किये जाते हैं।

9. अपील स्वीकार की जाती है। लागत के लिए कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी निखिल कुमार नाड (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।